परियोजनाओं की स्वीकृति से लेकर कार्यादेश तक सभी प्रक्रियाओं को स्ट्रीम लाइन करें- भजनलाल

राज उन्नति की बैठक में खाटू श्याम जी मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए

जयपुर, 19 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क सहित, जनसुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता के कारण देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ''राज उन्नति'' की छठी बैठक में कहा कि आमजन को

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की छठी बैठक में अधिकारियों दिशा-निर्देश दिए।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने पर व जन सुविधा की आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक पट्टा देने के प्रकरण में यूआईटी सचिव सहित 6 कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए।**

योजनाओं और विकास परियोजनाओं का निरन्तर लाभ मिलना चाहिए। निविदा प्रक्रिया में देरी या किसी भी अन्य कारण से इनमें रूकावट आई तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने सांगानेर में सीईटीपी के पम्पिंग स्टेशन और पाइप-लाइन के काम में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर मुआयना करें और शीघ्रता से काम पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि बडी परियोजनाओं में स्वीकृतियां, भूमि अधिग्रहण, निविदा प्रक्रिया और कार्यादेश जारी करने में लम्बा समय लगता है। उन्होंने मुख्य सचिव को इन प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन कर परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने श्रीगंगानगर जिले में एक ही भूमि के दो पट्टे जारी किए जाने पर, तथा जनसुविधा हेतु आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के प्रकरण में यूआईटी सचिव सहित, इस प्रकरण में संलिप्त आधा दर्जन से अधिक कार्मिकों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जिलेवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 7 विभागों की 8 परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं को मिशन मोड पर पूर्ण जिम्मेदारी से तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग और आरएसआरडीसी के अधिकारी निर्धारित ब्लू प्रिंट के अनुसार कार्य करते हुए खाटूश्याम जी मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करें।

उन्होंने सचिवालय में स्थानाभाव को देखते हुए, जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन स्थापना की कार्ययोजना की समीक्षा की तथा आरएसआरडीसी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज उन्नति की पूर्व बैठकों में मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना की प्रगति की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि हर माह होने वाली राज उन्नति की बैठक में मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से सीधे संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समय में समाधान किया जाता है।

पार्टी की सदस्यता छोड़ने पर संसद की सदस्यता भी चली जाती है- अभिषेक बनर्जी

नई दिल्ली, 19 जून। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि तृणमूल से अलग होने की बात कहने वाले धड़े को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान स्पष्ट कहता है कि पार्टी की सदस्यता छोड़ने

- **तृणमूल नेता ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अलग होने वाले धड़े को मान्यता नहीं देने का अनुरोध किया**

पर संसद की भी सदस्यता चली जाती है।

अभिषेक बनर्जी को इससे पहले 15 जून को लोकसभा अध्यक्ष से मिलना था। लेकिन कोलकाता में ईडी के समन के कारण मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें आज 5 बजे मिलने का समय दिया था। मुलाकात के दौरान अभिषेक के साथ कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रा और डेरेक ऑ ब्रायन भी थे।

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने बताया कि उन्होंने पार्टी से अलग होने की बात कहने वाले धड़े को मान्यता नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके पक्ष में दो तर्क रखे। उन्होंने कहा कि पार्टी के अलग समूह बनाने वाले सदस्यों में से कुछ ने दूसरी पार्टी जॉइन की है। ऐसे में वे तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे।

नीट री-एग्ज़ाम अभ्यर्थियों के लिए एनटीए ने एडवायज़री जारी की

एडवायज़री में ड्रैस कोड के अलावा कौन सी वस्तुएं ले जा सकते हैं, कौन सी नहीं, यह भी बताया गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 जून। नैशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को होने वाले री-एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है, जिसमें परीक्षा केन्द्रों पर पालन किए जाने वाले ड्रेस कोड, अनुमति प्राप्त वस्तुएं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे परीक्षा के सुचारु और सुरक्षित संचालन के लिए सभी निर्देशों का पालन करें।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं- पानी की पारदर्शी बोतल परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बारिश में भीगने या किसी अन्य नुकसान से बचाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में ले जा सकते हैं। उम्मीदवार आस्था से जुड़े वस्त्र या प्रतीक पहन सकते हैं, जैसे धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि। लेकिन, इसके लिए उन्हें समय से पहले परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करना होगा, ताकि उचित जांच (फ्रिस्किंग) की जा सके। बेहतर होगा कि हल्के कपड़े पहनें, लेकिन आवश्यकता होने पर उम्मीदवार फुल स्लीव कपड़े या ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उनकी अतिरिक्त सुरक्षा जाँच होगी। इसी प्रकार, चप्पल और कम हील वाले जूते पहनना बेहतर है। लेकिन हाई हील जूते भी पहने जा सकते हैं, किन्तु इन उम्मीदवारों की अतिरिक्त जांच हो सकती है।

- **दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड को प्लास्टिक के पाउच में रख सकते हैं, पर किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रोनिक उपकरण, मोबाइल फोन, इयर फोन, स्मार्ट वॉच, बड़े बैल्ट बकल, धातु के आभूषणों आदि पर रोक है।**
- **इसके अलावा अभ्यर्थी चाहे तो धार्मिक चिन्ह कलावा, पगड़ी, हिजाब आदि पहन सकता है, पर इसके लिए उन्हें निर्धारित समय से पहले आना होगा ताकि उनकी तलाशी प्रक्रिया हो सके।**
- **हाई हील के जूते-चप्पल भी पहने जा सकते हैं और पूरी बाजू के वस्त्र या गर्म कपड़ों की भी अनुमति है, पर इनकी भी विशेष तलाशी होगी।**

एनटीए ने परीक्षा हॉल में इन वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगाई है: मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, धातु की वस्तुएं, बड़े बेल्ट बकल, भारी आभूषण तथा अन्य ऐसी वस्तुएं, जो सुरक्षा जांच में बाधा डाल सकती हैं परीक्षण एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले, सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य रूप से तलाशी (फ्रिस्किंग) ली जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच समय पर पूरी हो सके और अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके।

अमेरिका-ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हुई। ईरान ने लेबनान में हिंसा और हमलों को रोकने की शर्त के उल्लंघन की ओर इशारा किया, जिसे समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक माना गया था।

इसके बाद, ईरान जिनेवा वार्ताओं से अलग हो गया, वार्ता में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति वेंस शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड जाने वाले थे। ईरान के हटने के बाद वेंस को अपना स्विट्ज़रलैंड दौरा रद्द करना पड़ा और स्थिति फिर से पहले जैसी अनिश्चित हो गई है।

इज़रायल और हिज़्बुल्लाह, दोनों ही ईरान और अमेरिका के बीच की वार्ता प्रक्रिया से स्वयं को बाहर महसूस कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लगभग अंतिम चरण में था। इज़रायल का मानना था कि उसे शामिल नहीं किया गया, जबकि हिज़्बुल्लाह को लगा कि उसका समर्थक रहा ईरान उसके हितों को नज़रअंदाज़ कर समझौता कर रहा है।

वार्ता के बाधित होने से विश्व और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं और लोगों की खुशहाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। युद्ध और तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से तेल की आपूर्ति रुक गई थी, जिससे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई थीं।

भारत भी ईरान संकट से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि तेल और खासकर एलएनजी (ससोई गैस) की आपूर्ति लगभग बंद हो गई थी। युद्ध शुरू होने के बाद रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे भारतीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया।

आज एक टैंकर भारत पहुँचा है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते तेल लेकर आया है। शुक्रवार को 25 जहाज़ इस जलमार्ग से गुज़रे, जो पहले की तुलना में बड़ा सुधार है, जब लगभग कोई आवाजाही संभव नहीं थी। ईरान ने कहा है कि वह इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों को मुफ्त समुद्री सेवाएँ प्रदान करेगा।

अमेरिका-ईरान समझौते के अनुसार, समुद्री मार्ग पूरी तरह से खोला जाना था और ईरान बिना किसी शुल्क के जहाज़ों को गुजरने देगा। यह वही व्यवस्था थी जो युद्ध शुरू होने से पहले थी।

चौदह बिंदुओं वाले इस समझौते में ईरान की परमाणु कार्यक्रम ने आगे न बढ़ाने की प्रतिबद्धता, नुकसान की भरपाई और ईरानी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण कोष, और अमेरिका द्वारा सभी प्रतिबंध हटाने का प्रावधान शामिल था।

यह समझौता ईरान को कई रियायतें देता है, जिसमें सभी प्रतिबंधों का हटना और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बहाल होना शामिल है। लेकिन अब हिज़्बुल्लाह की कार्रवाई के कारण ईरान इन लाभों को खोने की स्थिति में है।

दूसरी ओर, इज़रायली सरकार पर दक्षिणपंथी समूहों का भारी दबाव है, जो इज़रायली सैनिकों की मौत के लिए हिज़्बुल्लाह को कठोर सज़ा देने की मांग कर रहे हैं।

दोनों पक्षों का रुख सख्त होने के कारण, शांति प्रक्रिया के बाधित होने की आशंका और बढ़ गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन आज

नई दिल्ली, 19 जून। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और उससे जुड़े विवादों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर छात्र आत्महत्याओं के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी ने 20 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर

- **पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री को छात्र आत्महत्याओं पर खुला पत्र लिखा।**

प्रदर्शन का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि हाल के दिनों में परीक्षा संबंधी तनाव और कथित पेपर लीक की घटनाओं के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या की है। उन्होंने मांग की कि ऐसे छात्रों के परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।

पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, कल यानी 20 जून से जंतर-मंतर पर छात्र और समर्थक एकत्र होंगे।

पार्टी का कहना है कि देशभर से छात्र इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं।

कांग्रेस के साथ विलय का सवाल ही नहीं- उद्धव ठाकरे

मुंबई, 19 जून। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी के विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब हमने 30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय नहीं किया, तो फिर कांग्रेस के साथ विलय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अपनी पार्टी के छह लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भावुक होते हुए कहा कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद मेरा संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मैं इस जिम्मेदारी के लिये सही आदमी नहीं हूं, उसी दिन यह पद छोड़ दूंगा।

- **उद्धव ठाकरे ने स्थापना दिवस पर कहा कि अगर पार्टी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो पद छोड़ दूंगा।**

उद्धव ठाकरे ने भाजपा और कांग्रेस की राजनीति की तुलना करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे हमेशा से तीखे राजनीतिक मतभेद रहे हैं। विचारों की यह लड़ाई जगजाहिर है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी शिवसेना को जड़ से खत्म करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत, भाजपा आज शिवसेना का नामोनिशान मिटाने पर तुली हुई है।

राहुल अब मुस्कुराकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)?

तमिलनाडु में कांग्रेस को एक नया सहयोगी मिल गया है और कई दशकों बाद कांग्रेस राज्य की सत्ता का हिस्सा बनी है।

मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं हैं और अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस के मुस्लिम, दलित और कमजोर वर्गों के वोटों की आवश्यकता है।

लालू यादव भी अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है।

पिछले एक वर्ष में हुए इन बदलावों ने विपक्ष के बीच राहुल गांधी की स्थिति और छवि को मजबूत करने का काम किया है।

शिक्षा क्षेत्र, नीट, सीबीएसई, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के हालिया हमलों को नई पीढ़ी, यानी जनरेशन-ज़ैड का समर्थन मिल रहा है। यह वही युवा वर्ग है, जो उभरते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से नाराज़ तथा निराश है।

कांग्रेस के अधिक से अधिक कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी को भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अब वे इसे मुस्कुराकर स्वीकार कर रहे हैं।

उन्होंने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया, लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। तब से अब तक उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी, कठिन और उतार-चढ़ाव से भरी रही है, जिसमें उपलब्धियों से अधिक असफलताएं रही हैं। लेकिन आज उनके 56वें जन्मदिन के समारोह में वे जिस आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे दिखाई दिए, उससे स्पष्ट था कि पार्टी के भीतर और बाहर, दोनों जगह वे अब अपनी स्थिति को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हैं।

संभव है कि वे अगले एक-दो दिन में विदेश यात्रा पर चले जाएं, लेकिन पिछले वर्ष से वे अपना जन्मदिन कांग्रेस पार्टी के साथ ही मना रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा की हर समस्या ताकत से हल नहीं होती- उपराष्ट्रपति वैंस

अमेरिका-ईरान समझौते पर इज़रायल की आलोचनाओं पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी

वॉशिंगटन, 19 जून। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच 108 दिनों तक चले युद्ध के बाद अमेरिका-ईरान परमाणु समझौता वार्ता को लेकर इज़रायल की आलोचनाओं पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्या को ताकत का इस्तेमाल कर हल नहीं किया जा सकता।

तुर्किए की सरकारी संवाद समिति अनाडोलू एजेंसी के अनुसार, एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि इज़रायल में इस समझौते को लेकर जो घबराहट और विरोध देखने को मिल रहा है, वह काफी हद तक अविश्वास और गलतफहमियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से इज़रायल का विश्वसनीय साझेदार होने का प्रमाण दिया है और यह मानना कि वॉशिंगटन ने कोई खराब समझौता किया है, तथ्यों से मेल नहीं खाता।

जेडी वैंस ने कहा कि इज़रायल की राजनीतिक व्यवस्था और जनता का एक बड़ा वर्ग इस समझौते को लेकर बेहद

- **तुर्किये की सरकारी संवाद एजेंसी को इन्टरव्यू में जेडी वैंस ने कहा कि इज़रायल में इस समझौते पर घबराहट और विरोध काफी हद तक अविश्वास व गलतफहमियों पर आधारित है।**

संवेदनशील है। उन्होंने विशेष रूप से इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच का उल्लेख करते हुए कहा कि जो नेता इस समझौते की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके पास वैकल्पिक समाधान क्या है।

उन्होंने कहा, ''आप 90 लाख लोगों का देश हैं। आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर समस्या को केवल लोगों को मारकर या ताकत का इस्तेमाल कर हल नहीं कर सकते।''

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि यह समझौता न केवल इज़रायल बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और दुनिया के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। उनके अनुसार, इस प्रक्रिया ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक कमजोर किया है और तेहरान को ऐसी रियायतें देने की स्थिति में पहुंचाया है, जो कुछ महीने पहले तक असंभव लगती थीं।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का बयान ऐसे समय में आया है जब इज़रायल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जारी हैं।

स्टालिन ने भी राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखा: ''भारत के विचार, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा के लिए हमारा साझा संकल्प हमें मार्गदर्शन देता रहेगा-यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है, और हम इसे साथ मिलकर तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जीत नहीं मिलती।''

यह उत्तर राहुल गांधी की ओर से उस अलग हुए सहयोगी के लिए एक संधि संदेश (ऑलिव ब्रान्च) माना जा रहा है, खासकर उस स्थिति में, जब कांग्रेस ने तमिलनाडु चुनावों के बाद टीवीके के साथ जाने का निर्णय ले लिया है।

कांग्रेस के इस कदम से नाराज डीएमके ने पार्टी से संबंध तोड़ लिए हैं और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना ली है। पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी भाग नहीं लिया और लोकसभा अध्यक्ष को यह पत्र भी लिखा है कि उसे सदन में नई बैठक व्यवस्था चाहिये, क्योंकि वह कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना नहीं चाहती।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नए मित्र जोसेफ विजय ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं और उन्हें ''भाई'' कहा। इससे स्टालिन द्वारा 2025 में राहुल के जन्मदिन पर दी गई शुभकामना याद आ गई।

विजय ने लिखा: ''आप, जो हमारे महान राष्ट्र भारत के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाते रहते हैं, मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, आपके सभी प्रयासों में सफलता और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट सेवा की कामना करता हूँ।''

राहुल गांधी ने विजय को जवाब देते हुए लिखा: हम संविधान और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हैं-और साथ मिलकर हम तमिलनाडु के लोगों के कल्याण, गरिमा और आकांक्षाओं के लिए काम करते रहेंगे।

जहाँ स्टालिन और विजय के पोस्ट कांग्रेस के साथ उनके बदलते संबंधों को दिखाते हैं, वहीं राहुल गांधी के जवाब भी एक अलग कहानी कहते हैं।

विजय को उन्होंने तमिलनाडु स्तर पर काम जारी रखने का आश्वासन दिया, जबकि स्टालिन को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विचार की रक्षा का साझा संकल्प का संदेश दिया।

यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डीएमके राहुल गांधी के ''एकता'' के आ ान को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करेगी। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं और वह विपक्षी राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। खासकर तृणमूल और यूबीटी सेना के विघटन के बाद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए डीएमके के समर्थन के बिना प्रमुख भाजपा विधेयकों को रोकना कठिन होगा।

आने वाले सप्ताह यह बताएंगे कि स्टालिन भाजपा की विपक्षी दलों को विभाजित करने के कुत्सित खेल को कैसे देखते हैं और क्या वे मोदी-शाह के साथ मिलकर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ लेने के बजाय, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं।

शासन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को पहली बार जमानती वारंट जारी करते हुए 12 जून को तलब किया था, लेकिन कार्यालय बंद होने की वजह से वारंट की तामील नहीं हो सकी। ऐसे में अगली सुनवाई पर बेंच ने फिर से आईएएस को जमानती वारंट जारी करते हुए 1 जुलाई को तलब किया है।

पिछली सुनवाई पर बेंच ने कहा कि हमने विभाग के शासन सचिव अंबरीश कुमार को सम्मन जारी करते हुए 8 जून को बेंच के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। सम्मन की तामील होने के बावजूद, शासन सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही अनुपस्थिति का कोई कारण बताया गया। यह न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। ऐसे में शासन सचिव को जमानती वारंट जारी किए जाते हैं।

'राम मंदिर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा के लिए नुकसानदेह दिख रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टी के अपने नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया है। विवाद तब और बढ़ गया, जब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने दावा किया कि कम से कम 7 करोड़ रुपये की दान राशि का गबन किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अदालतों से इन आरोपों पर संज्ञान लेने की अपील की है, जबकि भाजपा के कुछ नेताओं ने भी इस विवाद को और हवादी है।

भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें दान राशि के कथित दुरुपयोग की जानकारी है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका विवरण देने से इनकार कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शिता की मांग की है।

उन्होंने दान, खर्च, संपत्तियों, बैंक खातों और भूमि लेन-देन का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करने की मांग करते हुए कहा कि मंदिर में दान देने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी भेंट का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

इस बीच, नृपेन्द्र मिश्रा ने नकदी, सिक्कों और कीमती धातुओं सहित विभिन्न प्रकार के दानों के प्रबंधन में गंभीर कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रबंधन व्यवस्था के दो मूल आधार, ईमानदारी और निगरानी होते हैं, लेकिन इस मामले में दोनों स्तरों पर विफलता दिखाई दी है। पूर्व नौकरशाह ने कहा कि इस पूरे मामले से उन्हें बहुत दुख हुआ है, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब राम मंदिर प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है।

जहाँ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि धन के गायब होने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसी महीने उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया।

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में बैठने वाला डमी परीक्षार्थी गिरफ्तार

आरोपी राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा में लैब असिस्टैंट है और मूल प्रत्याशी की जगह परीक्षा में बैठा था

जयपुर, 19 जून। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने के मामले में कार्रवाई करते हुए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र कुमार मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा में बैठा था। चौंकाने वाली बात यह है कि महेन्द्र कुमार स्वयं सरकारी कर्मचारी है और जालौर जिले के राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले की जांच के दौरान, महेन्द्र कुमार (30), निवासी खिरोड़ी, जिला जालौर, की भूमिका सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है तथा पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

- **एसओजी के अनुसार, मध्यस्थ रामहंस मीना के जरिए सत्य प्रकाश मीना और महेन्द्र कुमार के बीच 6 लाख रूपए में डमी के रूप मे परीक्षा देने का सौदा हुआ। महेन्द्र कुमार ने सत्य प्रकाश के स्थान पर सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान की परीक्षा दी।**

जांच में सामने आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) भर्ती परीक्षा में मूल अभ्यर्थी सत्य प्रकाश मीना (32), निवासी मोहनपुरा जिला गंगापुर सिटी, ने स्वयं परीक्षा नहीं दी थीं। उसने परीक्षा पास करने के लिए डमी परीक्षार्थियों की मदद ली थी।

एसओजी के अनुसार, मध्यस्थ रामहंस मीना के जरिए सत्य प्रकाश मीना और महेन्द्र कुमार के बीच छह लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। इसके तहत, 29 जनवरी 2023 को भरतपुर स्थित श्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केन्द्र पर महेन्द्र कुमार ने सत्यप्रकाश मीना के स्थान पर सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा दी थी।

एसओजी जांच में यह भी सामने आया कि डमी अभ्यर्थियों की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण कर सत्यप्रकाश मीना का वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान विषय) पद पर चयन हो गया था। लेकिन आरपीएससी में शिकायत पहुंचने के कारण उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका। एसओजी इस मामले में मुख्य अभ्यर्थी सत्य प्रकाश मीना को 28 दिसंबर 2023 को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908